



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, बुधस्तिवार, मई 22, 2003/ज्येष्ठ 1, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2003/JYAISTHA 1, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2003

सं. 9/आर ई-03/2002—2007

फा. सं. 01/94/180/26-पीएन/एएम 03/पीसी-IV.—निर्यात और आयात नीति, 2002—2007 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.27 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

“तथापि, जहाँ अप्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क लगता है, उसपर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। यह सुविधा अग्रिम लाइसेंस (वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस), वार्षिक अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक जरूरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस), मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस (विशेष अग्रदाय लाइसेंस), मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस (मध्यवर्ती लाइसेंस) सहित सभी अग्रिम लाइसेंसों को उनके जारी होने की तिथि से नियमित करने से संबंधित सभी लम्बित मामलों के लिए उपलब्ध होगी।”

2. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.8.4 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

“तथापि, जहाँ सीमा शुल्क का भुगतान ईपीसीजी योजना के अधीन किया जाना है, ईपीसीजी लाइसेंस जारी होने की तिथि पर ध्यान दिए बिना निर्यात दायित्व की कमी को नियमित करने के लिए उसपर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा।”

3. सार्वजनिक सूचना संख्या 54 (आर.ई 2000)/1997-2002 दिनांक 7.2.2001 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो कि गुजरात राज्य के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में स्थित इकाई के निर्यात दायित्व में बढ़ोत्तरी करने से संबंधित है। उक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 1 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा गया है।

“तथापि, सीमाशुल्क अधिसूचना 169/90 दिनांक 3.5.1990 और 160/92 दिनांक 20.4.92 के तहत जारी ई पी सी जी लाइसेंसों के संबंध में सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 31.3.2004 तक निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई जाएगी। जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के सामने लाइसेंसों के बारे में गलत बयानी/धोखा धड़ी के मामले आए हैं वहाँ निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे लाइसेंसों के संबंध में जहाँ न्यायिक आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।”

4. सीमाशुल्क अधिसूचना 110/95 दिनांक 5.6.95 के तहत जारी ई पी सी जी लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंसधारक 31.3.2004 तक निर्यात दायित्व के विस्तार के लिए पात्र माना जाएगा बशर्ते कि लाइसेंसधारक, जो पहले निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करने में असफल रहा है, निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करता है और 30 सितम्बर, 2004 तक आयात की तारीख से उस पर 15% साधारण ब्याज सहित पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में सीमाशुल्क का विवरण देते हुए बैंक गारण्टी प्रस्तुत करें। ऐसी बैंक गारण्टी 31.3.2005 तक वैध होगी।

(क) स्तर धारक होने के कारण विधिक वचन बद्धता सुविधा के पात्र अथवा अन्य सभी आवेदकों को बैंक गारण्टी प्रस्तुत करना होगी। बढ़ाई गई अवधि में निर्यात दायित्व को पूरा न कर पाने की स्थिति में बैंक गारण्टी जब्त कर ली जाएगी।

(ख) बैंक गारण्टी सहित अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को 30 जून, 2003 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां निर्यात दायित्व सार्वजनिक सूचना की इस तारीख से पहले किन्तु निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के बाद पूरा किया गया हो तो ऐसे निर्यात को नियमित करने के प्रयोजन के लिए निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरा किया गया माना जाएगा। ऐसे निर्यातक को बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) ऐसे मामलों में जहाँ पहले से निष्पादित बैंक गारण्टी के अन्तर्गत 15% साधारण ब्याज सहित पूरे न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में सीमाशुल्क शामिल है और

यह 2005 तक वैध है, अलग से बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं दिया जाएगा और लाइसेंस धारक को पहले से निष्पादित बैंक गारण्टी के ब्यौरों सहित 30.6.2003 को अथवा उससे पहले आवेदन करना होगा।

(ड.) यदि बैंक गारण्टी सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ निष्पादित की गई है तो इस संबंध में 30 जून, 2003 को अथवा उससे पहले संबंधित सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) ऐसे मामलों में जिनमें सार्वजनिक सूचना संख्या 5 दिनांक 6.4.99 या सार्वजनिक सूचना संख्या 3 दिनांक 31.3.2001 के अनुसार बैंक गारंटी पहले से ही निष्पादित की जा चुकी है तथा वह वैध है तो इसकी अवधि 31.3.2005 तक बढ़ाई जा सकती है इसमें सीमाशुल्क तथा उस पर 30.9.2004 तक ब्याज पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में शामिल होगा। इस संबंध में दस्तावेज 30.6.2003 तक या उससे पहले जमा करने होंगे।

(छ) ऐसे मामलों में जिनमें लाइसेंस धारक 31.3.2004 से पहले की अवधि के लिए निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन करता है, तो इसकी मंजूरी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी तथा ऐसे मामलों में बैंक गारण्टी एक वर्ष के लिए वैध होगी, यह अवधि निर्यात दायित्व के लिए माँगी गई अवधि के अतिरिक्त होगी। तथापि, ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने के लिए पहले से किए गए आवेदन के अलावा आगे अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ज) तथापि, ऐसे लाइसेंसों के बारे में निर्यात दायित्व की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकरणों की नज़र में कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी देखने में आई है। इसके अलावा ऐसे लाइसेंसों के संबंध में, जहाँ पहले से ही न्यायिक आदेश जारी किए जा चुके हैं, निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(झ) ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया गया है तथा लाइसेंस धारक ने इस सार्वजनिक सूचना के तहत सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, न्यायिक प्रक्रिया 30.6.2003 के बाद शुरू की जाएगी।

5. परिशिष्ट-23 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे -

सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल के प्रमाणपत्र के अनुलग्नक के आखिर में दी गई टिप्पणी को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

टिप्पणी 1 - इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ पंजीकरण संख्या सहित सनदी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

टिप्पणी 2 - निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन, सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर की मंजूरी के लिए केवल आवेदन के साथ ही अनुलग्नक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

6. सार्वजनिक सूचना संख्या 8 दिनांक 14.5.2003 का शुद्धिपत्र।

सार्वजनिक सूचना संख्या 8 दिनांक 14.5.2003 के पैरा 8 को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:-

पैरा 4.6 (घ)(iv) के बाद उप पैराग्राफ को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा:-

उत्पादन शुल्क प्राधिकारी के साथ पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक जिसने पिछले वर्ष 1 करोड़ रुपये या अधिक का निर्यात किया है और उपर्युक्त श्रेणी (ख) में आता है उसके अग्रिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर विधिक वचनबद्धता की शर्त लगाई जाएगी बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में किये गये निर्यातों/आपूर्तियों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 200% से अधिक न हो। 200% से अधिक की हकदारी वाले लाइसेंस, 200% हकदारी से अधिक मूल्य पर 100% बैंक गारण्टी के अधीन होंगे। तथापि दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें निर्यात दायित्व को पूरा करना और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति दर्शाया गया हो, को प्रस्तुत करने पर हकदारी को खाते में पुनः जमा किया जाएगा।

जिन निर्यातकों ने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में प्रत्येक वर्ष निर्यात किया है और उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आते हैं उनपर अग्रिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 25 प्रतिशत बैंक गारण्टी की शर्त लगायी जाएगी बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में किये गये निर्यातों/आपूर्तियों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 200% से अधिक न हो। 200% से अधिक की हकदारी वाले लाइसेंस, 200% हकदारी से अधिक मूल्य पर 100% बैंक गारण्टी के अधीन होंगे। तथापि, दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें निर्यात दायित्व को पूरा करना और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति दर्शाया गया हो, को प्रस्तुत करने पर हकदारी को खाते में पुनः जमा किया जाएगा।

उपर्युक्त (घ) या (ग) और (घ) दोनों के अधीन आने वाले आवेदक के सम्बंध में अग्रिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर 25 प्रतिशत बैंक गारंटी की शर्त लगायी जाएगी बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य घरेलू कारोबार के 200 प्रतिशत या आपूर्तियों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो से अधिक न हो। 200 प्रतिशत हकदारी से अधिक के लाइसेंस, 200 प्रतिशत हकदारी से अधिक मूल्य पर 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के अधीन होंगी। तथापि, दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें निर्यात दायित्व को पूरा करना और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति दर्शाया गया हो, को प्रस्तुत करने पर हकदारी को खाते में पुनः जमा किया जाएगा।

उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, व्यापारी निर्यातक (स्तरधारियों और पीएसयू को छोड़कर) को 100 प्रतिशत बैंक गारंटी सहित अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एल. मानसिंह, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd May, 2003

No. 9/RE-03/2002—2007

F. No. 01/94/180/26-PN/AM-03/PC-IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Export and Import Policy, 2002—2007, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1):—

1. The following shall be added in paragraph 4.27 of the Handbook of Procedure:

“However, wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, the same shall be paid alongwith interest @15% per annum thereon. This facility shall be available to all pending cases of regularisation of bonafide default advance licences irrespective of the date of its issuance including Advance licence (Advance Licence for physical exports), Annual Advance Licence (Advance Licence for annual requirement), Advance Licence for deemed exports (Special Imprest Licence), Advance Licence for Intermediate supply (Intermediate licence)”.

2. The following shall be added in paragraph 5.8.4 of the Handbook of Procedure:

“However, wherever Customs duty is to be paid under EPCG scheme, on account of shortfall in export obligation for regularisation for bonafide default, the same shall be paid alongwith interest @15% per annum thereon. This facility shall be available to all pending cases of regularisation of EPCG licences irrespective of the date of its issuance”.

14/1845/03-2

3. Attention is invited to public notice no. 54(RE-00)/1997-2002 dated 7.2.2001 relating to grant of EO extension in respect of units located in the areas affected by earthquake in the State of Gujarat. The following shall be added at the end of paragraph 1 of the said public notice.

“However EPCG licences issued under Customs notification 169/90 dated 3.5.1990 and 160/92 dated 20.4.92 shall be given export obligation extension upto 31.3.2004 by the licensing authority subject to terms and conditions mentioned in the public notice. No extension in export obligation shall be allowed in respect of the licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the licensing authorities. Further, in respect of licences where adjudicating orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.”

4. In respect of EPCG licences issued under Customs notification 110/95 dated 5.6.95, the licence holder shall be eligible for extension of EO period upto 31.3.2004 provided the licence holder who has failed to complete his export obligation within the earlier stipulated time period, applies for extension of export obligation period and submits a bank guarantee covering the Customs duty in proportion to the unfulfilled export obligation together with 15% simple interest thereon from the date of import upto 30th Sept, 2004. Such bank guarantee shall be valid upto 31.3.2005.
 - a) The bank guarantee shall be required to be submitted by all applicants including those eligible for LUT facility being status holders or otherwise. The bank guarantee shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period.
 - b) The request for extension alongwith BG shall be filed with the concerned licensing authority on or before 22nd August, 2003.
 - c) In cases where the export obligation has been fulfilled prior to this date of public notice but outside the prescribed EO period, such exports shall be deemed to have been made within the prescribed EO period for the purpose of regularisation of the case. Such exporter need not submit bank guarantee.
 - d) In cases where bank guarantee has already been executed with the concerned licensing authority covering the Customs duty in proportion to the unfulfilled EO together with 15% simple interest thereon and the same is valid till 31.3.2005, no separate BG shall be insisted upon and the licence holder shall be required to make a request for EO extension to the concerned licensing authority on or before 22nd August, 2003 alongwith details of BG already executed.
 - e) In case the BG has already been executed with the Customs authority, a certificate from the concerned Asstt. Commissioner of Customs and Central Excise shall be

furnished to this effect alongwith a request for EO extension to the concerned licensing authority on or before 22nd August, 2003.

- f) In cases where the Bank Guarantee has already been executed In terms of Public Notice No 5 dated 06.04.1999 or Public Notice No. 3 dated 31.3.2001 and is valid, the same may be extended upto 31.03.2005 covering the Customs duty in proportion to the unfulfilled export obligation together with 15.% simple interest thereon from the date of import upto 30th Sept, 2004. The licence holder shall submit a proof regarding extension of BG alongwith a request for EO extension to the concerned licensing authority on or before 22nd August, 2003.
- g) In cases where the licence holder applies for export obligation extension for a period prior to 31.3.2004, the same shall also be granted by the licensing authority and in such cases, the BG shall be required to be valid for a period of one year in addition to the period of export obligation sought for. However in such cases, no further extension in EO period beyond the period already applied for shall be allowed.
- h) However, no extension in export obligation shall be allowed in respect of the licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the licensing authorities. Further, in respect of licences where adjudicating orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.
- i) In such cases where the export obligation has not been completed and the licence holder has not availed the facility accorded under this Public Notice, adjudication proceedings shall be initiated after 22nd August, 2003.

5. The following amendment shall be made in Appendix-23

The Note given at end of annexure to the certificate of Chartered Accountant/Cost and work Accountant shall be amended to read as under:

Note.1: Each page of this annexure is to be signed by the Chartered Accountant with his registration number.

Note 2. The annexure shall be required to be furnished only with the application for grant of Export House, Trading House, Star Trading House, Super Star Trading House status.

6. Corrigendum to Public Notice No.8 dated 14.5.2003

Paragraph 8 of the Public Notice No.8 dated 14.5.2003 shall be corrected to read as under:

The sub-paragraph after paragraph 4.6 (d)(iv) shall be amended to read as under:

In respect of manufacturer exporters registered with excise authority with export of Rs.1 crore or above in preceding year falling in category (b) above, LUT condition shall be imposed on the CIF value of advance licence(s) provided the CIF value does not exceed 200% of the FOB/FOR value of exports/supplies made in the preceding licensing year. Licence beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on the value exceeding 200% entitlement. However, the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfilment of export obligation and realisation of foreign exchange.

In respect of exporters who have exported in each of the preceding three licensing years and exporters falling in category (c) above, the 25% BG condition shall be imposed on the CIF value of advance licence(s) provided the CIF value does not exceed 200% of the FOB/FOR value of exports/supplies made in the preceding licensing year. Licence beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on the value exceeding 200% entitlement. However, the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfilment of export obligation and realisation of foreign exchange.

In respect of applicant falling under d) above or falling under c) and d) both, the 25% BG condition shall be imposed on the CIF value advance licence(s) provided the CIF value does not exceed 200% of the domestic turnover or 200% of the FOB/FOR value of supplies, whichever is higher. Licence beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on the value exceeding 200% entitlement. However, the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfilment of export obligation and realisation of foreign exchange.

Notwithstanding anything stated above, merchant exporters (other than status holders and PSUs) shall be issued advance licence requiring them to provide 100% BG.

This issues in public interest.

L. MANSINGH, Director General of Foreign Trade